

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 19 मार्च, 2008

विषय:- जिला न्यायालय, हरिद्वार के वाहन संख्या-यू०पी०-10बी-6300 एवं यू०पी०-10बी-6363 के प्रतिस्थापन के आधार पर नये वाहन को क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 950/यू०एच०सी०/एडमिन-बी/2008, वाहन दिनांक 17.3.2008, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला न्यायालय, हरिद्वार के वाहन संख्या-यू०पी०-10बी-6300 एवं यू०पी०-10बी-6363 के प्रतिस्थापन के आधार पर नये Ambassador Grand 1800 ISZ वाहन को क्रय किये जाने हेतु प्रोफार्मा इनवायस की लागत पर रु० 4,18,957/- प्रतिवाहन की दर से 02 वाहनों को क्रय किये जाने हेतु कुल रु० 8,37,914/- (आठ लाख सैतीस हजार नौ सौ चौदह रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) शासकीय वाहन के क्रय हेतु अनुमन्य व्यापार कर में छूट हेतु फार्म डी निष्पादित कर क्रय की कार्यवाही की जाय । स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग न होने की स्थिति में धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय ।
- (2) उक्त वाहन के क्रय में स्टैन्डर्ड एक्सेसरीज के अलावा अन्य एक्सेसरीज हेतु धनराशि सम्मिलित नहीं है ।
- (3) वाहन के क्रय में डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों पर किया जाय ।
- (4) वाहन की निष्प्रयोज्यता से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही (निष्प्रयोज्य घोषित करना, वाहन की नीलामी एवं अर्जित राशि को राजकोष में जमा करना आदि) वाहन क्रय की स्वीकृति के तीन माह के अन्दर पूर्ण कर, उक्त कार्यवाही के पूर्ण करने के समस्त साक्ष्य सहित शासन को इसी अवधि में उपलब्ध करा दी जाय । यदि उक्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण न करने के फलस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व में कोई हानि होती है, तो उसकी वसूली सम्बन्धित पद धारक से की जायेगी ।
- (5) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।
- (6) व्यय उसी मद में किया जावेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारो/मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-1522/XXVII(5)/2007, दिनांक 19.3.08 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या : 47-दो(2)/XXXVI(1)(2)/2007-08-1-दो(2)/07-टी०सी०-11-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- जिला न्यायाधीश, हरिद्वार ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार ।
- 5- वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(के०पी०पाटनी)

अनुसचिव ।